

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2009/भाद्र 11, 1931

No. 284]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2009/BHADRA 11, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

क. मामले की पृष्ठभूमि

सं. 15/22/2008-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में यथासंग्रहित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 6-11-2003 की अधिसूचना सं. 14/3/2003 द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ उप शीर्ष 29392140 के अंतर्गत आने वाले चीन जन.गण. में मूल के या वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और भारत सरकार द्वारा दिनांक 15-12-2003 की अधिसूचना सं. 177/2003-सी.शु. के तहत इस प्रकार का अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 15 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 14/3/2003-डीजीएडी के द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए और भारत सरकार ने दिनांक 30-8-2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 84/2004 के तहत इस प्रकार का निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया था।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, जिसमें मै. इप्का लेबोरेटरीज लि., मुंबई शामिल है, द्वारा इस आशय का अनुरोध किए जाने के बाद चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (सी क्यू पी) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। इस अनुरोध के आधार पर यह कि इस प्रकार के शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने का अनुरोध किया है।

3. समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार 3 सितम्बर, 2008 को एक सार्वजनिक सूचना सं. 15/22/2008-डीजीएडी जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया और जिसके तहत लागू शुल्क को सतत रूप से जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात

की जांच करने कि शुल्क समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ।

## ख. प्रक्रिया

### 4. इन कार्रवाइयों के निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- (i) समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर और आवश्यक सूचना मांगते हुए घरेलू उद्योग, संबद्ध देश में समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा ज्ञात आयातकों को अधिसूचित किया;
- (ii) नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास को इस अनुरोध के साथ जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया कि वह निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें;
- (iii) उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा चीन के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी;
- (iv) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2004-मार्च, 2005, अप्रैल 2005-मार्च, 2006, अप्रैल 2006-मार्च, 2007 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल थी;
- (v) संगत सूचना मंगाने के लिए नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को भेजी गई थी:

1. मै. चोंग क्विंग कांग ली फार्मास्यूटीकल कं. लि., चीन जन.गण.

2. मै. चानझोंऊ विनसन फार्मास्यूटीकल कं. लि., चीन जन.गण.

उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत में इनमें से किसी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया ।

- (vi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना तथा आयातक प्रश्नावली भेजी गई थी :

1 मेडीकेम बायोटेक लिमिटेड	मै. साउथ इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट 8 प्रा. लि.
86-87 सेक्टर - 61, आई आई ई सिदकुल	श्रीनगर
हरिद्वार, उत्तराखंड	विजयवाड़ा 520 007

	9 मै. माइक्रोलेक्स लि.
2 सिनकॉम फॉर्म्यूलेशन (इंडिया) लि.	सं. 67/68 ए, तीसरा फेज
256-257, सेक्टर-1, इंडस्ट्रियल एरिया	पीन्या इंड एरिया
पीतमपुर	बंगलौर 506 058
3 एक्वाली रेमीडीज प्रा. लि.	10 मै. अत्रा फार्मास्यूटीकल्स लि.
संभव बेयर हाउसिंग	एच-19, एमआईडीसी वालुज
गोडाउन सं. 108, 109, 110	औरंगाबाद 431 133
बिल्डिंग सं. एफ,	(ए/सी मर्क लि.)
रेहनाल ग्राम पंचायत रोड रेहनाल ग्राम	
भिवांडी	11 यूनीमैक्स लेबोरेटरीज
	प्लॉट नं. 7, सेक्टर- 24
4 मै. श्रेय लाइफ साईस प्रा. लि.	फरीदाबाद 121 005
रुड़की 13, 14, 15, रायपुर	
पो. ऑ. भगवान पुर	12 कंकर्ड ड्रग्स लिमिटेड
रुड़की - 467 661	भेषजीय इकाई
उत्तराखंड	सं. 3-11-1/1 एल. बी. नगर
	हैदराबाद
5 निकोलस पीरामल इंडिया लि.	
प्लॉट सं. 67-70, सेक्टर- 2	13 कॉस्मे फार्मा लि.
पीतमपुर, धार	38/14 वाची वाड़ी (वीटादेव)
म. प्र. 454 775	सवर्ण, बायकोलिम
	गोआ 403 529
6 मै. फ्लेमिंगो फार्मास्यूटीकल लि.	
आर-662, टी. टी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया	14 बेयर क्रॉप साईस लि.

रबाले, न्यू मुंबई 400 701	कोलसेट रोड, थाणे
7 मै. सेफ पेरेंटरल्स लि.	15 मै. इस्टर्लिंग लैब
गोल्लापट्ट 522 408	57, सिप्काट ईड कॉम्प्लैक्स
गुंदूर जिला. (आ.प्र.)	होसूर -635 126 (तमिलनाडु)

(vii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आईबीआईएस के आंकड़ों के अतिरिक्त वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए आयातों के सौदेवार आंकड़े मांगे गए थे। विचाराधीन उत्पाद अध्याय-29 के उप शीर्ष 29392140 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

(viii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा।

(ix) घरेलू उद्योग का घटक होने के कारण मै. इप्का लेबोरेटरीज लि., मुंबई में क्षति संबंधी सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का संभावित/आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया ताकि पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की जा सके और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत निकाली जा सके और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की इस दृष्टि से जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा;

(x) नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 5 अगस्त, 2009 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समस्त हितबद्ध पार्टियों को अवसर भी प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का निवेदन किया गया था। हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है;

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए समस्त विचारों और किए गए अनुरोधों पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।

(xii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को किया जा रहा है और उन पर प्राप्त टिप्पणियों की विधिवत जांच अंतिम जांच परिणामों में की जाएगी।

(xiii) हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पार्टियों के समक्ष नहीं किया गया है। जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाली पार्टियों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

(xiv) जहां कहीं किसी हितबद्ध पार्टी ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

(xv) \*\*\* यह चिन्ह इस विवरण में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार इसे गोपनीय ही माना है।

## ग. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

### ग.1. घरेलू उद्योग के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

(i) वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा कि पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित किया गया है।

(ii) मूल जांच के दौरान उत्पाद की विशेषताओं में कोई खास परिवर्तन या विकास नहीं हुआ है और इस समय इस उत्पाद का उत्पादन कर विश्व भर में उसकी बिक्री की जा रही है।

(iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के मुद्दे की विस्तृत जांच की गई थी और इसकी पुष्टि की जानी अपेक्षित है।

(iv) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री ई एम एम ई तथा नोवाल्डियामाइन हैं। जहां ई एम एम ई का उपयोग अन्य उत्पादों में भी होता है, वहां नोवाल्डियामाइन का एकमात्र उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है। दूसरे शब्दों में नोवाल्डियामाइन का उत्पादन तब नहीं होगा जब क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का उत्पादन नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा समूची क्षति अवधि के दौरान चीन से नोवाल्डियामाइन का आयात किया जा रहा था। वस्तुतः याचिकाकर्ता कंपनी के अधिकारी चीन का दौरा करते रहे और वे नोवाल्डियामाइन उत्पादक के निकट संपर्क में रहे। उन्हें नोवाल्डियामाइन हेतु चीन के बाजार की पूरी जानकारी है और यह भी जानकारी है कि नोवाल्डियामाइन का चीन में उत्पादन घरेलू बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी है कि चीन की कंपनी द्वारा नोवाल्डियामाइन का उत्पादन उत्पाद की भारतीय जरूरत से काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। इससे स्पष्ट तौर पर चीन में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के सतत उत्पादन की पुष्टि होती है।

## ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

6. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. मूल जांच और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद क्लोरोक्वीन फॉस्फेट (जिसे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है। मूल जांच में उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट एक कार्बनिक रसायन है और इसका प्राथमिक उपयोग मलेरिया की औषधि के रूप में किया जाता है। यह एक सफेद या लगभग सफेद रवादार पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक, जल में मुक्त रूप से विलेय, एल्कोहल में कम विलेय, ईथल तथा मैथानोल है। इसमें एन हाइड्रस पदार्थ के संबंध में संगणित 98.5% से अनधिक और 101.0% समतुल्य से अनधिक एन-4 (7-क्लोरोक्वीनोलिन-4-वाई एल)-एन-1, एन 1-डाई इथाइलपेन्टेन-1, 4-डाइमिनेबिस (डाई-हाइड्रोजन फॉस्फेट) होता है। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के उत्पादन हेतु मध्यवर्ती 4:7 डाइक्लोरोक्वीनोलिन एथोक्सी मेथाइलिन ईस्टर (ईएमएमई) के साथ मेटाक्लोरोएनीलिन की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है जिसके बाद अल्कालिन हाइड्रोलिसिस तथा क्लोरीनेशन किया जाता है। इस मध्यवर्ती को नोवालिडियामाइन के साथ आगे और संघनित किया जाता है और क्लोरोक्वीन फॉस्फेट हासिल करने के लिए प्राप्त क्लोरोक्वीन की फॉस्फोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है।"

विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी हितबद्ध पार्टी की ओर से कोई तर्क न दिए जाने के मद्देनजर प्राधिकारी का प्रस्ताव विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करने का है जैसा कि ऊपर विचार किया गया है और उसमें उल्लेख किया गया है।

8. विचाराधीन उत्पाद क्लोरोक्वीन फॉस्फेट अध्याय-29 के उप-शीर्ष 29392140 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट और चीन से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट में कोई खास अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन से निर्यातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग अदल-बदल कर करते आ रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. से आयातित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना जा रहा है।

**घ. घरेलू उद्योग का आधार एवं क्षेत्र****घ.1. घरेलू उद्योग के विचार**

10. वर्तमान जांच में मै. इप्का लेबोरेटरीज लि. ने घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दाखल की है। याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है। मै. इप्का लेब्स का उत्पादन घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उनका उत्पादन "कुल पात्र भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा" बनता है और इसलिए याचिका में पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर आधार संबंधी जरूरत की पूर्ति होती है।

**घ.2. आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार**

11. "घरेलू उद्योग" और उसके आधार के बारे में किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पार्टी ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है।

**घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

12. भारत में संबद्ध उत्पाद के दो उत्पादक हैं अर्थात् मै. इप्का लेबोरेटरीज लि., मुंबई तथा मै. मंगलम ड्रग्स एंड आर्गेनिक्स लि., मुंबई। पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने हेतु वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन मै. इप्का लेबोरेटरीज लि., मुंबई द्वारा दायर किया गया है। मै. इप्का लेबोरेटरीज लि. के उत्पादन का हिस्सा भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक (77%) बनता है।

13. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में (ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा)।

इस जांच के प्रयोजनार्थ मै. मंगलम ड्रग्स एंड आर्गेनिक्स लि. ने प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस प्रकार ऐसी किसी स्थिति में जिसमें समग्र घरेलू उत्पादकों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं होती है, वहां प्राधिकारी के लिए उन उत्पादकों पर विचार करना अपेक्षित होता है, जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। अतः विधिक उपबंधों तथा वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै. इप्का लेबोरेटरीज लि., मुंबई, नियमावली के अर्थ के भीतर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग है।

**ड. पाटन मार्जिन****ड.1 निर्धारण की कार्य प्रणाली****सामान्य मूल्य****ड.1 घरेलू उद्योग के विचार:**

14. घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त विचार निम्नानुसार हैं :

(क) चीन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । किसी भी देश ने विस्तृत मूल्यांकन मापदंडों को अपनाने के बाद चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा प्रदान नहीं किया है । यूरोपीय आयोग तथा अमरीका द्वारा पिछले तीन वर्षों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । यूरोपीय संघ और अमरीका विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं । भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है ।

(ख) नियमों में 15 शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें से प्रत्येक शर्त को इच्छुक निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा करने में पूरा करना होता है और ऐसे दावे की पुष्टि हेतु आवश्यक संगत सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने होते हैं । याचिकाकर्ता ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में दावा किया है । याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक ऐसी समस्त 15 शर्तें पूरी नहीं करते हैं तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित है ।

(ग) चीन के उत्पादकों के लिए भारत एक उचित प्रतिनिधि देश है । न केवल भारत को एक प्रतिनिधिक देश के रूप में माने जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक एवं पर्याप्त सूचना प्राप्त होगी अपितु यह मानने के भी वास्तविक आधार नहीं हैं कि भारत एक उचित प्रतिनिधि देश होगा । अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी भारत को एक उचित प्रतिनिधिक देश माना गया है ।

(घ) संबद्ध वस्तु का उत्पादन केवल चीन और भारत में किया जाता है । इस वजह से भी भारत को उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में मानना उचित होगा ।

(ङ) इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत, और (ख) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जा सकत है । तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा लाभ हेतु विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है ।

(च) ऐसी स्थिति में जहां पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो और जहां घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो अथवा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना हो, वहां लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए । वर्तमान मामले में वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन से उत्पाद के पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।



(छ) ऐसी स्थिति में जिसमें विद्याराशीम उत्पाद का वर्तमान में कोई निर्यात नहीं हुआ है, तहां संभावना के निर्धारण हेतु कोई कामूनी प्रावधान नहीं है। विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई पद्धति से यह पता चलता है कि निम्नलिखित में से किसी आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन जांच की वर्तमान अवधि में कोई निर्यात न होने की स्थिति में पाटन की संभावना के निर्धारण का आधार बन सकता है -

क. मूल जांच के समय निर्धारित पाटन मार्जिन

ख. वर्तमान क्षति अवधि में किए गए निर्यातों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन

ग. तीसरे देशों की किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन

घ. निर्यातकों द्वारा की गई आपूर्तियों के प्रस्तावों पर आधारित पाटन मार्जिन

उ. उन कीमतों पर आधारित पाटन मार्जिन जिस कीमत पर भारतीय बाजार में प्रचलित कीमत को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में सामग्री का निर्यात किया जा सकता है।

(ज) याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों को हुए निर्यातों पर आधारित पाटन मार्जिन को छोड़कर उपर्युक्त सभी मापदंडों के आधार पर पाटन की संभावना का दावा किया है। जहां तक तीसरे देशों को हुए निर्यातों पर आधारित पाटन मार्जिन का संबंध है, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसका इस तथ्य के मद्देनजर निर्धारण नहीं किया जा सकता कि तीसरे देशों को चीन से हुए निर्यातों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि चीन का सीमाशुल्क क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के लिए निर्दिष्ट सीमाशुल्क वर्गीकरण में स्पष्ट उपांतरण करता है और इसलिए चीन सीमाशुल्क के आंकड़े अन्य देशों को हुए निर्यात के संबंध में उपलब्ध नहीं हैं। आयातक देशों के व्यापार आंकड़ों पर भी इस तथ्य के मद्देनजर भरोसा नहीं किया जा सकता कि इन देशों द्वारा भी इस सीमाशुल्क वर्गीकरण के लिए आंकड़ों की सूचना नहीं दी जा रही है और उन्होंने अन्य सीमाशुल्क वर्गीकरण में इस सीमाशुल्क वर्गीकरण को शामिल कर दिया है। याचिकाकर्ता ने ऐसे प्रमुख देशों, जहां क्लोरोक्वीन फॉस्फेट की खपत की जा रही है, के संबंध में इस बात की पुष्टि करते हुए अनकॉमट्रेड के आधार पर साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि इस सूचना से विद्याराशीम उत्पाद के किसी सौदे का पता नहीं चलता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने इन देशों को स्वयं निर्यात किया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि व्यापार के आंकड़ों में किसी भी हालत में शून्य प्रविष्टि नहीं दर्शायी जा सकती।

## ४.2 निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

15. निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के निर्धारण के बारे में किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पार्टी ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

## ४.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

#### चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य

17. चीन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी भी देश ने विस्तृत मूल्यांकन मापदंडों को अपनाने के बाद चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा प्रदान नहीं किया है। प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है बशर्ते प्रतिवादी निर्यातक नियमों में निर्धारित प्रत्येक शर्त को पूरा कर दें। चूंकि चीन जन.गण. के किसी निर्यातक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन लागत पर विचार करने के बाद किया गया है।

18. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों/घरेलू बिक्री तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ हेतु विधिवत समायोजित घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर किया है। तदनुसार कारखाना स्तर पर सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डॉ. प्रति कि.ग्रा. निकाला गया है।

#### चीन जन.गण. में निर्यात कीमत

19. चीन के किसी भी निर्यातक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। किसी अन्य हितबद्ध पार्टी ने ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जिसका उपयोग निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु किया जा सके।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आई बी आई एस तथा डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के आयातों का पता नहीं चलता है। यहां तक कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों से भी जांच अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के निर्यातों का पता नहीं चलता है। जांच अवधि के दौरान क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के आयात के अभाव में निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

21. हितबद्ध पार्टियों की ओर से किसी सहयोग तथा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त पैरा 14(छ) में की गई व्याख्या के अनुसार अन्य पद्धति के आधार पर निर्यात कीमत के निर्धारण का दावा किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में सूचना के अभाव में अन्य आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण भ्रामक हो सकता है।

जांच अवधि में न हुए वर्तमान आयात के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन से उत्पाद का सतत पाटन नहीं हो रहा है और संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

### पाटन मार्जिन

22. यद्यपि सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है परंतु संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत उपलब्ध न होने के कारण पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।

### च. क्षति निर्धारण हेतु कार्यपद्धति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

#### च.1. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

##### च.1.1. घरेलू उद्योग के विचार

23. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने अनेक तर्क दिए हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है। मुख्य-मुख्य तर्क ये हैं कि :

- (क) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। यह आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप है। आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग स्वयं अपनी स्थिति में सुधार कर सका। तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की सर्वाधिक संभावना है।
- (ख) वर्तमान प्रस्तावित जांच अवधि में चीन से विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हो सकता है। तथापि, इस अवधि के दौरान कोई आयात न होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि उत्पाद का पाटन किए जाने की संभावना नहीं है तथा इससे केवल यह सिद्ध होता है कि सतत पाटन नहीं हो रहा है।

- (ग) वर्ष 2005-06 तक आयात कम स्तर पर जारी रहे परंतु अवधि की समाप्ति तक वे उत्तरोत्तर समाप्त हो गए। तथापि, जहां कहीं निर्यात किए गए हैं, वे पाटित कीमतों पर हुए हैं। इसके अलावा, चीन के निर्यातकों ने क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के लवणों का निर्यात किया है। लवण की कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की कीमत के रूप में विचार किए जाने की स्थिति में पाटन की पुष्टि होती है (यद्यपि पर्याप्त मूल्यवर्धन होगा)।
- (घ) क्षति अवधि के दौरान भारत के लिए किए गए पोटलदानों के संबंध में निर्यात कीमतें घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम रही है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में सकारात्मक कीमत कटौती होने की संभावना है।
- (ङ) लवणों की आयात कीमत पर विचार करते हुए आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रहने की संभावना है जिससे कीमत कटौती हो रही है।

#### च.1.2. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं आदि के विचार

24. चीन जन.गण. के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया है। न ही किसी निर्यातक की ओर से क्षति एवं कारणात्मक संबंध सहित वर्तमान जांच के किसी पहलू के बारे में कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है।

#### च1.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

25. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

26. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट

सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संभव आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों, नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित आन्तरिक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

27. प्राधिकारी ने क्षति की जांच के बारे में दिए गए तर्कों को नोट किया है और उठाए गए मुद्दों पर उचित स्थानों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने तथ्यों एवं वित्तबद्ध पार्टियों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की तथ्यात्मक जांच की है।

28. वर्तमान क्षति के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों तथा कीमतों एवं लाभप्रदता पर उसके संभावित प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की आगे और जांच की है।

#### क) मांग का निर्धारण

29. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की व्यापारी बिक्री एवं आबद्ध खपत तथा समस्त स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप किया है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में देखी जा सकती है :

आंकड़े क्रिया. में

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग की बिक्री	कि.ग्रा.	364540	375260	442259	627358
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	121	172
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	कि.ग्रा.	101600	222330	192590	147190
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	219	190	145
आयात	कि.ग्रा.	71583	10750	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	15	0	0
मांग/खपत	कि.ग्रा.	5,37,723	6,08,340	6,34,849	7,74,548
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	118	144

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की मांग में 44% की वृद्धि हुई है।

**ख) आयात की मात्रा एवं बाजार हिस्सा**

30. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है :-

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ....."

31. आयात मात्रा तथा बाजार हिस्से के बारे में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	यूओएम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग की बिक्री	कि.ग्रा.	364540	375260	442259	627358
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	121	172
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	कि.ग्रा.	101600	222330	192590	147190
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	219	190	145
संबद्ध देश-चीन	कि.ग्रा.	70,658	6,250	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	8	0	0
अन्य देश	कि.ग्रा.	925	4500		
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	485	0	0
कुल आयात	कि.ग्रा.	71583	10750	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	15	0	0
मांग	कि.ग्रा.	537723	608340	634849	774548
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	118	144
मांग में बाजार हिस्सा					
➤ घरेलू उद्योग	%	67.79	61.69	69.66	81.00

➤ प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	103	119
➤ अन्य भारतीय उत्पादक	%	18.89	36.55	30.34	19.00
➤ प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	161	190
➤ संबद्ध देश-चीन	%	13.14	1.03	0.00	0.00
➤ प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	8	0	0
➤ अन्य देश	%	0.17	0.74	0.00	0.00
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	435	0	0
कुल	%	100%	100%	100%	100%

32. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के कारण वर्ष 2005-06 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतः पाटन एवं क्षति जारी रहने का कोई साक्ष्य नहीं है। तथापि, निर्णायक समीक्षा में पाटन जारी रहने के अभाव में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है जिसे इस जांच परिणाम प्रकटन विवरण में उचित स्थानों पर किया गया है।

### कीमत प्रभाव

33. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है।

"नियम 18 के उप नियम (2) में यथाउल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा कांक्षी मात्रा में बढ़ गई होती।"

34. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

(क) वर्ष 2004-05 में आयातों की मात्रा काफी अधिक रही थी और ये वर्ष 2005-06 तक निम्न स्तर तक जारी रही थी परंतु अवधि की समाप्ति तक ये उत्तरोत्तर पूर्णतः समाप्त हो गए। इसके अलावा, जब कभी निर्यात किए गए हैं तो यह पाया गया है कि ये सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए गए हैं।

(ख) जांच अवधि तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई आयात न होने के कारण जांच अवधि के लिए कीमत कटौती का निर्धारण नहीं किया जा सका। परंतु प्राधिकारी ने यह नोट किया कि

क्षति अवधि के दौरान भारत को किए गए पोत लदान के संबंध में आयात कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम रही है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने पर कीमत में कटौती होने की संभावनाएं हैं।

#### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

35. नियमावली के अनुबंध-II में अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर घाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

#### उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग

36. आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

	इकाई:	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग की बिक्री	किग्रा.				
व्यापारी	किग्रा.	244352	243961	231205	198695
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	95	81
आबद्ध	किग्रा.	120188	131308	198988	428663
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	166	357
निर्यात	किग्रा.	145926	226045	207165	205482
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	155	142	141
कुल बिक्री	किग्रा.	510486	601314	637359	832840
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	125	163
घरेलू उद्योग का उत्पादन	किग्रा.	525128	583477	596123	883098
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	148
क्षमता	किग्रा.	725000	725000	725000	725000



प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	72.43	80.48	82.22	121.81
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	148
आयात-चीन	किग्रा.	70,658	6,250	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	9	0	0

प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री (आबद्ध हस्तांतरण सहित) तथा क्षमता उपयोग में सतत वृद्धि हुई है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग अपनी मात्रा को बढ़ाने में समर्थ हुआ है।

### बाजार हिस्सा

37. घरेलू उद्योग तथा विभिन्न अन्य पार्टियों का भारत में मांग में हिस्सा निम्नानुसार रहा था:

आंकड़े % में

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
घरेलू उद्योग	67.79	61.69	69.08	81.00
अन्य भारतीय उत्पादक	18.89	36.55	30.92	19.00
संबद्ध देश-चीन	13.14	1.03	0.00	0.00
अन्य देश	0.17	0.74	0.00	0.00

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के कारण क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस संबंध में अधिकारकर्ता ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण आयातों के हिस्से में पर्याप्त गिरावट आई तथा घरेलू उद्योग के हिस्से में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने की स्थिति में आ गया।

### लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रभाव

39. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व एवं पश्चात लाभ/हानि, निवेश पर आय एवं नकद लाभ में सुधार हुआ है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3
3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3
3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3
3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3	3191 GI/09-3

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
लाभ/(हानि)					
बिक्री लागत - घरेलू	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	106
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	109	114
लाभ/(हानि)	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(161)	(105)	(67)
लाभ/(हानि)	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(161)	(99)	(54)
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(166)	(96)	(50)
नकद लाभ	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(166)	(96)	(51)
लगाई गई पूंजी पर आय	%	***	***	***	***

40. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रति इकाई घाटे में कमी आई है। पाटित आयातों की समाप्ति के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में क्रमिक सुधार हुआ है। लगाई गई पूंजी पर आय आधार वर्ष के दौरान ऋणात्मक \*\*\*% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक \*\*\* % हो गई।

41. नकद प्रवाह पर पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी ने नकद लाभ में प्रवृत्तियों पर विचार किया है क्योंकि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और कंपनी के नकद प्रवाह की स्थिति संबद्ध उत्पाद में उतार-चढ़ाव की संकेतक नहीं होगी। नकद प्रवाह का निर्धारण लाभ (कर पूर्व लाभ) में मूल्य ह्रास की राशि को जोड़कर किया गया है। इस प्रवृत्ति में उसी प्रवृत्ति का पता चलता है जैसी कि पाटित आयातों की समाप्ति के कारण लाभों के बारे में रही है।

#### मालसूची:

42. आधार वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान घरेलू उद्योग के पास तैयार उत्पादों का औसत स्टॉक शून्य था जो नीचे दर्शायी गई स्थिति के अनुसार वर्ष 2006-07 तथा जांच अवधि के दौरान बढ़कर 6133 किग्रा. हो गया :

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
औसत स्टॉक	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य	6133	6133

### रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता एक बहु उत्पाद कंपनी है और पाटनरोधी शुल्क लागू है। इन मापदंडों से क्षति का पता नहीं चलता है।

### वृद्धि

44. मात्रा एवं बिक्री मात्रा, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ प्रदत्ता, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह जैसे कीमत संबंधी मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक है।

### पाटन मार्जिन

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक था। जांच अवधि के दौरान वास्तविक निर्यात कीमत और संबद्ध देशों से वास्तविक आयात के अभाव में वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया गया है।

### पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है परंतु घरेलू उद्योग अभी भी घाटा उठा रहा है। अतः आगे और पूंजी निवेश जुटाना कठिन है।

### क्षति के बारे में निष्कर्ष

47. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण क्षति अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आई तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग एवं उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटे में पर्याप्त कमी आई परंतु घरेलू उद्योग अभी भी लाभ कमाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, निवेश पर आय आधार वर्ष के दौरान ऋणात्मक \*\*\*% से घटकर ऋणात्मक \*\*\*% हो गई।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में आई कमी और अंततः उनकी समाप्ति के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।

### अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

49. प्राधिकारी ने अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति, यदि कोई हो, को अलग करने के लिए नियमों में यथानिर्धारित कारणात्मक संबंध तथा कारणोत्तर कारकों के मुद्दे की जांच की है तथा इस संबंध में नियमों में निर्धारित निम्नलिखित सांकेतिक कारकों की जांच की गई है :

(क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा एवं कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु का उत्पादन केवल चीन और भारत में किया जाता है इसलिए तीसरे देशों से हुए पाटन के कारण क्षति से इंकार किया जाता है। वस्तुतः क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है और जांच अवधि में यह शून्य हो गया है।

(ख) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य भारती उत्पादकों द्वारा अपनाए गए कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं पाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार मौजूद नहीं है।

(ग) मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

विचाराधीन अवधि के दौरान समग्र मांग में कोई कमी नहीं आई है। अतः मांग में कोई संभावित कमी वह संकेतक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। खपत की पद्धति में परिवर्तन के बारे में हितबद्ध पार्टियों ने कोई तर्क नहीं दिया है और न ही यह पता चलता है कि खपत की पद्धति में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(ङ) निर्यात निष्पादन

क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री कमोबेश स्थिर रही है। तथापि, घरेलू बिक्री के संबंध में आंकड़ों की पृथक जांच की गई है।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
निर्यात बिक्री	कि.ग्रा.	145926	226045	207165	205482
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	155	142	141

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

पाटन एवं क्षति की संभावनाघरेलू उद्योग के विचार

50. वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है और प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होगी। वर्तमान प्रस्तावित जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हो सकता है। तथापि, इस अवधि के दौरान कोई आयात न होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि उत्पाद का पाटन किए जाने की संभावना नहीं है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि कोई सतत पाटन नहीं हुआ है। वस्तुतः निम्नलिखित से पाटन की संभावना की स्पष्ट तौर पर पुष्टि हो जाती है।

- (क) किए गए निर्यातों का पाटन - जब कभी चीन के उत्पादकों द्वारा निर्यात किया गया है तो वे संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुए हैं। ऐसा मामला होने के कारण पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (ख) चीन में कोई मांग नहीं है- इस उत्पाद की चीन में शून्य या नगण्य घरेलू मांग है। इस प्रकार चीन के उत्पादकों ने यह क्षमता स्थापित कर उसे निर्यातों के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित किए हुए हैं। भारत इस उत्पाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वस्तुतः चीन से हुए आयातों पर विगत में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण चीन के अनेक उत्पादकों ने अपना उत्पादन स्थगित कर दिया है। तथापि, चीन में इस समय कम से कम 3 ऐसे ज्ञात उत्पादक हैं जो अत्यंत कम स्तर पर अपने संयंत्रों का प्रचालन कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति इन उत्पादकों के अभूतपूर्व स्वागत से कम नहीं होगी।
- (ग) चीन के वैश्विक निर्यातों में गिरावट - यद्यपि, चीन के उत्पादक शून्य या नगण्य घरेलू खपत का सामना कर रहे हैं तथापि इस उत्पाद की वैश्विक मांग में भी गिरावट आई है। इस बात पर विचार करते हुए वस्तुतः यह स्वागत योग्य है कि इससे मलेरिया उन्मूलन होता है। तथापि, कार्यशील उत्पादकों के पास व्यावहारिक रूप से कोई स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय मांग नहीं बची है और वे अत्यंत कम क्षमताओं पर प्रचालन कर रहे हैं। ऐसा मामला होने के कारण शुल्क की समाप्ति से भारतीय बाजार के चीन की सामग्री से पट जाने की संभावना है।
- (घ) वर्तमान डीपीसीओ कीमत सामान्य मूल्य से काफी कम है। भारत सरकार ने उत्पाद की डीपीसीओ कीमत सावधानीपूर्वक निर्धारित की है जो अब चीन में इस उत्पाद के सामान्य मूल्य से काफी कम प्रतीत होती है। चूंकि कानून में उत्पाद की बिक्री डीपीसीओ से कम पर करने की अनुमति नहीं है, इसलिए चीन के उत्पादक पाटन का सहारा लिए बिना इस सामग्री का किसी भी हालत में निर्यात नहीं कर सकते।

उपर्युक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादक पाटन का सहारा लेंगे।

51. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध भी किए हैं कि :

- (i) संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और उन निर्यातकों को असहयोगी माना जाए।
- (ii) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के समस्त उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालनरत माना जाए।
- (iii) विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के क्षेत्र, याचिकाकर्ताओं के आधार तथा घरेलू उद्योग के क्षेत्र की पुनः पुष्टि की जाए।
- (iv) पाटन की संभावना का निर्धारण वर्तमान जाँच अवधि के दौरान किसी वास्तविक ज्ञात पोतलदान की जानकारी न होने की स्थिति में विभिन्न संभावित तरीकों पर विचार करने के बाद किया जाए।
- (v) निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना है।
- (vi) चीन से तीसरे देशों को हुए विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के बारे में कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में निष्कर्ष निकालने से पूर्व अन्य विकल्प पर विचार करें।
- (vii) जहाँ कहीं चीन से निर्यात किए गए हैं वहाँ वे पाटित कीमतों पर हुए हैं। इसके अलावा, चीन के निर्यातक क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के लवणों का निर्यात कर रहे हैं। यदि लवण की कीमत को विचाराधीन उत्पाद की कीमत माना जाता है (यद्यपि पर्याप्त मूल्यवर्धन होगा) तो संभावित पाटन की पुष्टि हो जाती है।
- (viii) भारत में विधायी अपेक्षाओं के कारण चीन के उत्पादक डीपीसीओ से अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री नहीं कर सकते। वस्तुतः उन्हें केवल कम कीमत पर ही बिक्री करनी होगी क्योंकि डीपीसीओ कीमत वह कीमत होती है जिस पर आयातित उत्पाद की देश में पुनः बिक्री की जा सकती है। जाँच अवधि के दौरान प्रचलित क्लोरोक्वीन फॉस्फेट की डीपीसीओ कीमत पर पाटन की संभावना की पुष्टि भी की जाती है।
- (ix) चीन में संबद्ध वस्तु की कोई खास खपत नहीं है।
- (x) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप आयातों में गिरावट आई है और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- (xi) चीन के उत्पादकों के पास क्लोरोक्वीन फॉस्फेट की मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और भारत इस उत्पाद के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है।
- (xii) चीन के उत्पादकों के पास बेशी क्षमता तथा क्लोरोक्वीन लवणों की आयात कीमत एवं डीपीसीओ कीमत पर विचार करते हुए पाटन की संभावना के मद्देनजर चीन से हुए आयातों के संबंध में शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।
- (xiii) संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को आगे और पाँच वर्ष की अवधि तक लागू रखना अपेक्षित है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

52. हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा अनुरोधों और हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों के जरिए अथवा अन्यथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद तथा वर्तमान पाटन एवं क्षति और पाटन एवं क्षति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (i) जांच अवधि तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान चीन से भारत को संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है इसलिए, कोई सतत पाटन नहीं हुआ है।
- (ii) घरेलू उद्योग ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा डब्ल्यू एच ओ क्षेत्र के पश्चिमी प्रशान्त देशों में सूचित मलेरिया के मामलों के आधार पर वर्ष 1990-2007 की अवधि के लिए आंकड़ों के बारे में लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2007 के लिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट से यह नोट किया गया है कि वर्ष 2007 के दौरान भारत के संबंध में मलेरिया के 1476562 मामलों की तुलना में चीन के संबंध में मलेरिया के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। भारत और चीन के अलावा, भूटान के संबंध में मलेरिया के 850 मामलों और कंबोडिया के संबंध में 59848 मामलों की सूचना दी गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में संबद्ध वस्तु की नगण्य मांग/खपत है जबकि भारत में संबद्ध वस्तु की भारी मांग है।
- (iii) चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात यद्यपि वर्ष 2005-06 से बंद हो गए हैं तथापि, चीन जन.गण. के निर्यातकों के पास अभी भी निपटान योग्य क्षमताएं हैं। ऐसी स्थिति में जब चीन में विचाराधीन उत्पाद की मांग वैश्विक बाजार में उत्पाद की घटती हुई मांग के साथ मौजूद नहीं है, उत्पादन की पर्याप्त क्षमताओं की मौजूदगी से संबद्ध देश से पाटन होने की संभावना बढ़ जाती है।

**अंतिम जांच परिणाम:**

53. हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों या उपर्युक्त जांच परिणाम में अन्यथा दर्ज अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान एवं संभावित पाटन एवं क्षति की स्थिति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

- (i) संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को असहयोगी माना जाता है।
- (ii) यद्यपि सतत पाटन हुआ है परंतु जब कभी जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से निर्यात हुए हैं तो वे घरेलू बिक्री कीमत से कम पर हुए हैं।
- (iii) वर्ल्ड ट्रेड एटलस पर उपलब्ध आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्राधिकारी ने यह पाया है कि विचाराधीन उत्पाद का पूर्व में आयात 8 अंकीय स्तर पर एक विशेष कोड अर्थात् 29392140, जो इस उत्पाद का विशिष्ट कोड है, के तहत किया जा रहा था। बाद में

प्राधिकारी ने इस विशिष्ट आईटीसी एचएस वर्गीकरण के अंतर्गत कोई निर्यात नहीं पाया है। तथापि, आईटीसी एचएस 293921 के साथ 6-अंकीय स्तर पर “कुनाइन” उत्पाद जिसमें विचाराधीन उत्पाद (क्लोरोक्वीन फॉस्फेट) भी शामिल है, के आयात की मात्रा 2004-05 के दौरान 76 एमटीएस के आसपास और 2006-07 के दौरान लगभग 70 एमटीएस रही थी। इससे यह पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात संबद्ध देश से 6-अंकीय स्तर पर लगातार होता रहा है। तथापि, जाँच अवधि के दौरान इन आंकड़ों में सूचित आयात केवल 4 मी. टन के हैं जिसे ऐसी कार्यनीति के रूप में माना जा सकता है कि आयातों की सूचना नहीं दी जा सके क्योंकि निर्यातकों को इस बात की जानकारी थी कि निर्णायक समीक्षा होने वाली है। इस सीमा तक तक मौजूदा पाटनरोधी उपाय की समाप्ति से चीन में कुल माँग से काफी अधिक बेशी क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए अन्य देशों के बजाए भारत में पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद को भेजने हेतु चीन के उत्पादकों के लिए आसान द्वार खुलने की प्रबल संभावना है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने आंकड़ों में आयातों को शामिल करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण कुल माँग की सही गणना नहीं की जा सकी और वस्तुतः कुल माँग की गणना घरेलू उद्योग की वाणिज्यिक बिक्री को लेकर ही की गई है।

- (iv) उपर्युक्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि विशिष्ट कोड के अंतर्गत भारत में संबद्ध वस्तु का अभी भी आयात किए जा रहे हैं और वर्तमान उपाय समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (v) इसके अलावा, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की संभावना है।

### भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

54. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि शुल्क जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय जारी रखे जाने से पाटन की पद्धति द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय जारी रखने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

55. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है और ऐसी स्थिति को बहाल करना है, जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से सम्बद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।



## सिफारिश

58. इस आशय का निष्कर्ष निकालने के बाद कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से हुए आयातों के कारण बाढ़न तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से हुए आयातों के संबंध में पाटनरोधी उपाय की अवधि बढ़ाना अपेक्षित है, तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को संशोधित करने की जरूरत नहीं है। अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 15 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 14/3/2003-डीजीएडी के तहत संस्तुत एवं 30 अगस्त, 2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 84/2004-सी.शु. के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क और जिसकी अवधि 16 अक्टूबर, 2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 108/2008-सी.शु. के तहत आगे और 2 सितम्बर, 2009 तक बढ़ाई गई है, को जारी रखने की सिफारिश करते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2009

## FINAL FINDING

**Subject : Sunset Review of Anti-Dumping Investigations concerning imports of Chloroquine Phosphate originating in or exported from China PR.**

## A. BACKGROUND OF THE CASE

No. 15/22/2008-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty on imports of Chloroquine Phosphate (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR falling under Customs Tariff Subheading 29392140, vide Notification No. 14/3/2003 dated 06-11-2003 and such provisional Anti-Dumping Duty was imposed by Government of India vide Notification No. 177/2003-Custom dated 15-12-2003. The Authority issued its final finding recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty vide Notification No. 14/3/2003-DGAD dated 15th July, 2004 and such definitive duty was imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 84/2004 dated 30-08-2004.

2. The Designated Authority initiated the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Chloroquine Phosphate (CQP) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as subject country) following a request to this effect by the Domestic Industry comprising of M/s Ipca Laboratories Ltd., Mumbai. The request was based on the grounds that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The petitioner claimed that *prima facie* evidence exists in this regard and have requested for the continued imposition of the anti-dumping duty on subject goods from the subject country.

3. Having satisfied on the basis of positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Designated Authority issued a Public Notice No. 15/22/2008-DGAD dated 3rd September, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Sunset Review investigation of the anti-dumping duties to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-Dumping Rules.

## B. PROCEDURE

4. In these proceedings the procedure described below has been followed :

(i) After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry, all known exporters/producers in the subject country and known importers, calling for questionnaire responses and necessary information in accordance with Rule 6(4);

(ii) The Embassy of China in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/ producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

(iii) Copy of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassy of China in accordance with Rules 6(3) supra.

(iv) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2007 to 31st March, 2008 (POI). However, injury analysis covered the periods April 2004-March 2005, April 2005-March 2006, April 2006-March 2007 and the POI.

(v) A copy of initiation notification alongwith exporters' questionnaires were sent to the following known exporters from subject country in accordance with the rule 6(4) to elicit relevant information:

1. M/s. Chong Qing Kang Le Pharmaceutical Co., Ltd., China PR.
2. M/s Changzhou Winsun Pharmaceutical Co. Ltd., China PR.

None of these exporters responded to the questionnaire in response to the above notification.

(vi) Initiation notification and importers questionnaire was sent to following known importers/consumers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4). None of the interested parties filed any questionnaire response.

	M/s South India Research
1 Medicamen Biotech Ltd	8 Institute Pvt.Ltd
86-87 Sector – 61, IIE sidcul	Sirinagar
Haridwar, Uttakhand	Vijayawada 520 007
	9 M/s Micro Labs Limited
2 Syncom Formulation(India)Ltd	No. 67/68 A, 3rd Phase
256-257, Sector –1, Industrial Area	Peenya Industrial Area
Pithampur	Bangalore 506 058
3 Aquati Remedies Pvt.Ltd	10 M/s Atra Pharmaceuticals Ltd
Sambhav Warehousing	H-19, MIDC Valuj
Godown No. 108, 109,110	Aurangabad – 431 133
Building No. F,	(A/C Merk Ltd)

Rehmal Gram Panchayat Road Rehmal Village	
Bhiwandi	11 Unimex Laboratories
	Plot No. 7, Sector - 24
4 M/s Shreya Life Sciences Pvt.Ltd	Faridabad 121 005
Roorkee 13,14,15, Raipur	
P.O. Bhagwanpur	12 Concord Drugs Ltd
Roorkee - 467 661	A Pharmaceuticals Unit
Uttarakhand	No. 3-11-1/1 L.B. Nagar
	Hyderabad
5 Nicholas Piramal India Ltd	
Plot No.67-70, Sector -2	13 Cosme Pharma Ltd
Pithampur, Dhar	38/14 Watchfi Wadi(Vtadev)
M.P. 454 775	Savarna, Bicholim
	GOA 403 529
6 M/s Flamingo Pharmaceutical Ltd	
R-662, T.T.C. Industrial Area	14 Bayar Cropscience Ltd
Rabale, New Mumbai 400 701	Kolshet Road, thane
7 M/s Safe Parenterals Ltd	15 M/s Sterling Lab
Gollapadu -522 408	57, Sipcot Industrial Complex
Guntur Dist. (A.P)	Hosur -635 126(T.N)

(vii) Transaction-wise data of imports for the period of investigation and preceding three years were called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) in addition to the IBIS data provided by the domestic industry. The product under consideration is classified under Chapter 29 under Sub-heading 29392140. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

(viii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties.

(ix) M/s. Ipca Laboratories Ltd., Mumbai, being constituent of domestic industry, submitted the injury information/data. The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible/necessary to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and to workout optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;

(x) In accordance with Rule 6(6), the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 5<sup>th</sup> August 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered in this finding;

(xi) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.

(xii) In accordance with Rule 16 of the anti-dumping Rules, the essential facts/basis considered for these findings are being disclosed to the known interested parties and comments received on the same would be duly examined in the final findings.

(xiii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever necessary, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

(xiv) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

(xv) \*\*\* in this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the authority under the Rules.

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'**

### **C.1. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

5. Following issues are raised by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

(i) Present review investigation is a sunset review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the previous investigations.

(ii) There is no material change or development in the product characteristics between the original investigation and product being produced and sold world-over at present.

(iii) The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product. The Issue of product under consideration and like article was examined in detail by the Designated Authority in the original investigations and is required to be confirmed.

(iv) EMME and Novaldiamine are the major raw materials required for production of the product under consideration. While EMME has application in other products as well, the only application of Novaldiamine is in a production of the product under consideration. In other words, Novaldiamine will not be produced if there is no production of Chloroquine Phosphate. The petitioner was importing Novaldiamine from China over the entire injury period. In fact, officials from the petitioner company keeps visiting China and are in close contact with the Novaldiamine producer. They are fully aware of the Chinese market for Novaldiamine and are aware that Novaldiamine is being produced in China in significant quantities for domestic sales. The petitioner is aware that the production of Novaldiamine by the Chinese company is far higher than Indian requirement for the product. This clearly establishes continued production of Chloroquine Phosphate in China.

### **C.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties**

6. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.

### **C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

7. The product under consideration in the original investigation as also in the present investigations is Chloroquine Phosphate (also referred to as subject goods). The product was defined in the original investigations as follows:

*"The product under consideration in the present petition is Chloroquine Phosphate. Chloroquine Phosphate is an organic chemical and primarily used as drug for Malaria. It is a white or almost white crystalline powder, hygroscopic, freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, ether and methanol. It contains not less than 98.5% and not more than equivalent to 101.0% N4 (7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diaminebis(di-hydrogen phosphate), calculated with reference to the anhydrous substance. For production of Chloroquine Phosphate intermediate 4:7 Dichloroquinoline is prepared by the reaction of Meta Chloro Aniline with Ethoxy Methylene Ester (EMME) followed by Alkaline Hydrolysis and Chlorination. This Intermediate is further condensed with Novaldiamine and Chloroquine obtained is treated with Phosphoric Acid to obtain Chloroquine Phosphate."*

In view of no argument from any interested party with regard to product under consideration, the Authority proposes to confirm the scope of the product under consideration as was considered above and as has been stated herein.

8. The product under consideration, *Chloroquine Phosphate*, is classified under Chapter 29 under Sub-heading 29392140. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

9. There is no significant difference in the Chloroquine Phosphate produced by the Indian industry and the Chloroquine Phosphate exported from China. Chloroquine Phosphate

produced by the Indian industry and exported from China are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Chloroquine Phosphate produced by the domestic industry and imported from China PR are being treated as like article in accordance with the Anti-Dumping Rules.

#### **D. Standing and scope of the Domestic Industry**

##### **D.1. Views Of the Domestic Industry**

10 In the present investigation, M/s. Ipca Laboratories Ltd. has filed the petition on behalf of domestic industry. Production of the petitioner constitutes a major proportion of total Indian production. The production of M/s IPCA labs accounts for more than 50 per cent of the total production of the like product produced by the domestic producers. Petitioner submitted that its production accounts for "a major proportion in total eligible Indian production" and therefore, petition satisfies the requirement of standing within the meaning of the anti dumping rules.

##### **D.2. Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested parties**

11. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to "domestic industry" and its standing.

##### **D.3. Examination by the Designated Authority**

12. There are two producers of the subject product in India, namely M/s. Ipca Laboratories Ltd., Mumbai and M/s. Mangalam Drugs and Organics Ltd, Mumbai. The present sunset review application for continued imposition of anti dumping duty has been filed by M/s. Ipca Laboratories Ltd., Mumbai. The production by M/s IPCA Laboratories Ltd. commands more than 50% share [77%] in Indian production.

13. Rule 2(b) under the Rules provides as follows:-

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case [such producers may be deemed] not to form part of domestic industry"*

For the purpose of this investigation M/s. Mangalam Drugs and Organics Ltd. has not provided the relevant information to the Authority. Thus, in a situation where information with regard to domestic producers as a whole is not available, the Rules require the Authority to consider those producers whose collective output constitutes a major proportion in the total domestic production. Therefore, having regard to the legal provisions and facts & circumstances of the present case, the Authority considers that M/s. Ipca Laboratories Ltd.,

Mumbai constitutes domestic industry for the purpose of the present investigations within the meaning of the Rules.

### **E. Dumping Margin**

### **E.1 METHODOLOGY OF DETERMINATION**

#### **NORMAL VALUE**

#### **E.1 Views of the Domestic Industry:**

14. The views expressed by the domestic industry are as follows —

- (a) China is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China after following elaborate evaluation parameters. China has been treated non-market economy by European Commission and United States in the past three years. European Union and United States are members of World Trade Organization. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy.
- (b) There are 15 conditions prescribed under the Rules each one of which an intending exporter has to satisfy in order to claim market economy treatment and the information and evidence relevant and necessary to establishment of such a claim. Petitioner has claimed China as non-market economy. Petitioner submits that, unless the responding Chinese exporters satisfy all such 15 conditions, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.
- (c) India is an appropriate surrogate country for Chinese producers. Not only consideration of India as a surrogate country would result in access to accurate and adequate information, there is no factual basis to consider that India would not be a proper surrogate country. India has been considered as an appropriate surrogate by other Investigating Authorities too.
- (d) The subject goods are produced only in China and India. On this account as well, it would be appropriate to consider India as an appropriate market economy third country.
- (e) The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and profit.
- (f) In a situation where the dumping continues or is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty and where the domestic industry continues to be injured or the injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty, the anti dumping duty in force should be continued further for a period of five years. In the instant case, dumping of the product from China is likely to recur, should the present anti dumping duty be revoked from China.
- (g) In a situation where there are no current exports of the product under consideration, there is no legal prescription for determination of likelihood. The practice followed by different countries suggests that dumping margin determined on any of the followings can form the basis for determination of likelihood of dumping in the event of no exports in the current period of investigation-



- a. Dumping margin determined at the time of original investigations;
  - b. Dumping margin determined in respect of exports made in the current injury period;
  - c. Dumping margin in respect of exports to third countries;
  - d. Dumping margin based on offers for supplies made by the exporters;
  - e. Dumping margin based on the prices at which material can be exported in the Indian market, having regard to the price prevailing in the Indian market.
- (h) The petitioner has claimed likelihood of dumping on the basis of all above parameters except dumping margin based on exports to third countries. With regard to dumping margin based on exports to third countries, petitioner claimed that the same could not be determined in view of the fact that there is no publicly available information with regard to exports from China to third countries. The petitioner claimed in this regard that China Customs apparently modified the Customs classification meant for Chloroquine Phosphate, and, therefore, China Customs data is not available in respect of export to other countries. Even trade data of the importing countries could also not be relied upon in view of the fact that even these countries are not reporting data for this customs classification and have merged the customs classification with other customs classification. Petitioner provided evidence based on UNCOMTRADE in respect of major countries where Chloroquine Phosphate is being consumed substantiating that the information did not show any transaction for the product under consideration. Since petitioner itself has exported to these countries, petitioner claimed that the trade data could not in any case show nil entries.

## **E.2 View of exporters/importers and other interested parties**

15. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to export price, normal value and determination of dumping margin

## **E.3 Examination by the Authority**

16. Under section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for*



profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

### **Normal Value in China PR**

17. China is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China after following elaborate evaluation parameters. The Authority has treated China as non-market economy unless the responding exporters satisfied each & every conditions prescribed under the Rules. Since none of the exporter from China PR responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed, the Authority has determined the Normal Value in respect of China PR under para 7 of Annexure I of Anti-dumping Rules, considering China PR as non-market economy. The normal value accordingly has been determined considering cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative expenses and reasonable profit.

18. The Authority has determined the normal value in China PR based on international prices of inputs/ domestic prices and conversion cost of domestic industry, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profit. Accordingly, the normal value at ex-factory level has been worked out as US\$ \*\*\* per Kg.

### **Export price in China PR**

19. None of the exporter from China PR responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed. None of the other interested parties have provided any other information that can be used for determination of export price.

20. The Authority notes that the information made available by IBIS and DGCI&S does not show imports of Chloroquine Phosphate. Even transaction wise data made available by DGCI&S does not show exports of Chloroquine Phosphate during POI and immediate previous year. In absence of import of chloroquine phosphate during POI, export price could not be determined.

21. In absence of any co-operation from interested parties and imports of subject goods during POI, domestic industry claimed determination of export price on the basis of other methods, as explained in para 14(g) above. Authority notes that, in absence of information on imports of subject goods from subject countries, export price determination on other basis may be misleading.

In view of no current exports in the period of investigation, the Authority holds that there is no continued dumping of the product from China and export price of subject goods could not be determined.

### **Dumping margin**

22. Though the normal value has been determined but in absence of export price availability of for subject goods, dumping margin has not been determined.

## **F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**

### ***F.I INJURY AND CAUSAL LINK***

#### ***F.1.1. Views of the domestic industry***

23. The domestic industry has raised a number of arguments with regard to injury and causal link, which are summarized below. The main arguments are that:

- (a) The performance of domestic industry improved over the injury period. This is consistent with the trend of decline in imports. The domestic industry could improve itself in the absence of imports. Injury to the domestic industry is, however, most likely in the event of revocation of anti dumping duties.
- (b) There may be no exports of the product under consideration in the present proposed investigation period from China PR. No imports during this period, however, do not establish that the product is unlikely to be dumped. It only establishes that there was no continued dumping.
- (c) Imports continued at lower levels till 2005-06, but ceased subsequently entirely towards the expiry of the period. However, whenever exports have been made, the same are at dumping prices. Further, the Chinese exporters have exported salts of Chloroquine Phosphate. Likely dumping is established even if salt price is considered as price of the product under consideration (even though there would be substantial value addition).
- (d) Import prices in respect of shipments made to India over the injury period have been significantly below the net sales realization of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Positive price undercutting is likely, should the present duties be revoked.
- (e) Considering the import prices of salts, landed price of imports is likely to be lower than the selling price of the domestic industry, thus causing price undercutting.

#### ***F.1.2. Views of exporters, importers, users etc***

24. There has been no response from any producer/exporter in China PR. Nor has any arguments been advanced on any aspect of the present investigations, including on injury & causal link from any exporters.

#### ***F.1.3. Examination by the Authority***

25. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the

effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

26. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the Anti Dumping Rules states as follows.

*"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."*

27. The Authority has taken note of the arguments on injury examination and addressed the issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.

28. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from the subject country on the domestic industry and its likely effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any. The Authority has further examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of anti-dumping duty.

**a) Assessment of Demand**

29. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of merchant sale and captive consumption of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below.

Figures in KG

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales of domestic industry	Kgs.	364540	375260	442259	627358
Trend	Indexed	100	103	121	172
Sales of Other Indian Producers	Kgs.	101600	222330	192590	147190
Trend	Indexed	100	219	190	145
Imports	Kgs.	71583	10750	0	0
Trend	Indexed	100	15	0	0
Demand/consumption	Kgs.	5,37,723	6,08,340	6,34,849	7,74,548
Trend	Indexed	100	113	118	144

The Authority notes that the demand of the product in the country has shown a positive trend and grew over the injury period. The demand for the product under consideration has increased by 44% as compared to the base year.

**b) Import Volume & market share**

30. With regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure-II (ii) of the Anti-dumping rules provides as under :-

*"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India .....*"

31. The information regarding the imports volume and market share is given in the following table:

	UOM	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales of Domestic industry	Kgs.	364540	375260	442259	627358
Trend	Indexed	100	103	121	172
Sales of Other Indian Producers	Kgs.	101600	222330	192590	147190
Trend	Indexed	100	219	190	145
Subject Country-China	Kgs.	70,658	6,250	0	0
Trend	Indexed	100	8	0	0
Other countries	Kgs.	925	4500		
Trend	Indexed	100	485	0	0
Total Imports	Kgs.	71583	10750	0	0
Trend	Indexed	100	15	0	0
Demand	Kgs.	537723	608340	634849	774548
Trend	Indexed	100	113	118	144
Market Share in Demand					
➤ Domestic industry	%	67.79	61.69	69.66	81.00
Trend	Indexed	100	91	103	119

► Other Indian Producers	%	18.89	36.55	30.34	19.00
Trend	Indexed	100	193	161	100
► Subject Country-China	%	13.14	1.03	0.00	0.00
Trend	Indexed	100	8	0	0
► Other countries	%	0.17	0.74	0.00	0.00
Trend	Indexed	100	435	0	0
Total	%	100%	100%	100%	100%

32. Authority notes from the above that the share of the domestic industry in demand increased significantly over the injury period except for the year 2005-06 on account of anti-dumping duties. Hence no continuation of dumping and injury is evident. However, in sunset review, in the absence of continuation of dumping, the Authority is required to evaluate the likelihood of dumping and injury in the event of revocation of anti-dumping duty, which has been done at appropriate place in this finding.

### **Price Effect**

33. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows

*"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which other wise would have occurred to a significant degree."*

34. In the present case, the Authority notes that:

- (a) Imports were significant in 2004-05 and continued at lower levels till 2005-06, but ceased subsequently entirely towards the expiry of the period. Further, whenever exports have been made, it has been found that the same were at prices below normal values.
- (b) Due to no imports during POI and immediate previous year, price undercutting can not be determined for POI but Authority noted that the import prices in respect of shipments made to India over the injury period have been significantly below the net sales realization of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Price undercutting is likely, should the present duties be revoked.

### **Economic Parameters relating to the Domestic Industry**

35. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an object examination of consequent impact of the imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products,

the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

**Production, sales, capacity and capacity utilization**

36. Actual production, capacity and capacity utilization of the domestic industry increased between the base year and the period of investigation as shown in the following table-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Sales of Domestic Industry					
Merchant	Kgs.	244352	243961	231205	198695
Trend	Indexed	100	99	95	81
Captive	Kgs.	120188	131308	198988	428663
Trend	Indexed	100	109	166	357
Exports	Kgs.	145926	226045	207165	205482
Trend	Indexed	100	155	142	141
Total Sales	Kgs.	510466	601314	637359	832840
Trend	Indexed	100	118	125	163
Production of domestic industry	Kgs.	525128	583477	596123	883098
Trend	Indexed	100	111	114	148
Capacity	Kgs.	725000	725000	725000	725000
Trend	Indexed	100	100	100	100
Capacity utilization	%	72.43	80.48	82.22	121.81
Trend	Indexed	100	111	114	148
Imports – China	Kgs.	70658	6250	0	0
Trend	Indexed	100	9	0	0

The Authority notes that there has been consistent increase in production, sales (including captive transfer) and capacity utilization over the injury period. Thus, the domestic industry has been able to improve its volumes after imposition of anti dumping duties.

### **Market share**

37. Share of the domestic industry and various other parties in demand in India was as under:

Figures in %

Particular	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Domestic industry	67.79	61.69	69.08	81.00
Other Indian Producers	18.89	36.55	30.92	19.00
Subject Country-China	13.14	1.03	0.00	0.00
Other countries	0.17	0.74	0.00	0.00

38. The Authority notes that the share of the domestic industry in total demand increased significantly over the injury period on account of anti dumping duties. In this regard, the petitioner has submitted that with the imposition of anti-dumping duties, the share of imports declined significantly and the share of domestic industry increased. The domestic industry is in a position to cater to the Indian demand.

### **Profit/loss, return on investment and cash flow**

39. The return on investment, profit/loss before and after interest, return on investment and cash profit has moved as shown in the table below:

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
<b>Profit /( Loss)</b>					
Cost of Sales - Domestic	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	106
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	109	114
Profit/( Loss)	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(161)	(105)	(67)
Profit/( Loss)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(161)	(99)	(54)



Profit before Interest and Taxes	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(166)	(96)	(50)
Cash Profit	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(166)	(96)	(51)
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***

40. The Authority notes from the above that the financial performance of the domestic industry has improved over the injury period. The per unit loss to the domestic industry has reduced during POI in comparison to base year. There is gradual improvement in the situation of the domestic industry after cessation of dumped imports. Return on capital employed improved from negative \*\*\*% during base year to negative \*\*\*% during POI.

41. In order to analyze the impact of dumped imports on cash flow, the Authority has considered the trends in cash profits, as the domestic industry is a multi product company and cash flow situation of the company would not be indicative of the situations in the subject product. The cash profit has been determined by addition of amount of depreciation to the profit (profit before tax). The trend shows the same trend as that of profits with the cessation of dumped imports.

#### **Inventories:**

42. Average stock of finished products with the domestic industry was nil during base year 2004-05 and 2005-06 and increased to 6133 Kg during 2006-07 and POI, as per position shown below:

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Average stock	Kgs.	Nil	Nil	6133	6133

#### **Employment, wages and productivity**

43. The Authority notes that since the petitioner is a multi product company and anti dumping duty is in place. These parameters do not show injury.

#### **Growth**

44. Growth of the domestic industry is positive in respect of volume as well as price parameters such as sales volume, production, capacity utilization, profitability, return on investment and cash flow.

#### **Dumping margin**

45. The Authority notes that the dumping margin determined in the previous investigation was quite significant. In absence of actual export price during POI in absence of actual import



from subject countries, the dumping margin in the present investigation has not be determined.

### **Ability to raise capital investments**

46. The Authority notes that though the position of the domestic industry has improved gradually but the domestic industry is still incurring losses, therefore, to raise further investment is difficult.

### **Conclusion on injury**

47. The imposition of anti dumping duties resulted in decline in imports and improvement in performance of the domestic industry during the injury period. The performance of the domestic industry improved in terms of production, sales, capacity utilization and productivity. Though the losses to the domestic industry has reduced substantially during injury period but still domestic industry is not in position to earn profit. Return on investment, however, reduced from negative \*\*\*% during base year to negative \*\*\*%.

48. The Authority notes that the performance of the domestic industry improved with decline and ultimately cessation of imports.

### **Other known factors and causal link**

49. The Authority examined the issue of causal link and other non-attributive factors as laid down in the Rules to segregate injury, if any, caused by other factors. In this regard, the following indicative factors as laid down in the Rules have been examined.

#### **(a) Volume and Prices of imports not sold at the dumped prices**

The Authority notes that since the subject goods are produced only in India and China, injury because of dumping from third countries is ruled out. In fact, share of imports from subject country has declined over the injury period and reached zero during the POI.

#### **(b) Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers**

The Authority has not found any trade restrictive practice followed by the domestic industry and other Indian producers. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market.

#### **(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**

There is no contraction in the overall demand during the period under consideration. Therefore, any possible decline in demand is not a factor, which could have caused injury to the domestic industry. There is no argument by interested parties regarding the change in the pattern of consumption, nor it appears that changes in the pattern of consumption could have inflicted the injury to the domestic industry.

#### **(e) Export performance**

Export sales of the domestic industry are more or less stable over the injury period. However, the data with respect to domestic sales has been examined separately.

3191 48/05-6

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Exports Sales	Kgs	145926	226045	207165	205482
Trend	Indexed	100	155	142	141

(f) Productivity of the Domestic Industry

Productivity of the domestic industry has gone up after the anti dumping duty levied on subject goods.

**Likelihood of dumping & injury**

**Views of the Domestic Industry**

50. The present investigation is a review investigation and the Authority is required to examine whether revocation of duty is likely to lead to recurrence of dumping and injury. There may be no exports of the product under consideration in the present proposed investigation period. No imports during this period, however, does not establish that the product is unlikely to be dumped. It only establishes that there was no continued dumping. In fact, the following clearly establishes likelihood of dumping.

- (a) Dumping in exports made – Whenever exports have been made by Chinese producers, the same have been below associated normal value. Such being the case, dumping is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duty.
- (b) No Chinese Demand – The product has zero or negligible domestic demand in China. Thus, Chinese producers have set up and holding these facilities only for the purpose of exports. India is one of the largest consumers of this product. In fact, past imposition of anti dumping duties on imports from China has led to a number of Chinese producers suspending their production. However, there are at least three known producers in China at present that have been operating their plants at extremely low levels. Under these circumstances, revocation of anti dumping duties would not be less than a red carpet welcome to these producers.
- (c) Decline in Chinese Global exports – While Chinese producers are faced with zero or negligible domestic consumption, global demand for this product has also declined. Indeed this is welcomed, considering that the same indicates eradication of Malaria. However, the surviving producers have been left with practically no local and international demand and have been operating at very low capacities. Such being the case, revocation of duty would result in instant flooding of Indian market with Chinese material.
- (d) Current DPCO price is far lower than normal value. Govt. of India has cautiously fixed the DPCO price of the product, which now happens to be significantly below the normal value of this product in China. Since the law does not allow selling of the product above DPCO, there is no way Chinese producers can export the material without resorting to dumping.

In view of the above, it is evident that Chinese producers would resort to dumping in the event of revocation of present anti dumping duties.

51. The domestic industry has also made following submissions on the disclosure statement:

- (i) That none of the exporters from subject country have responded to the Authority and those exporter may be treated as non-cooperative .
- (ii) That all producers/exporters of subject goods in China PR may be treated as operating under non-market environment.
- (iii) That the scope of the product under consideration & like article, Standing of the petitioners and scope of the domestic industry may be re confirm.
- (iv) That likelihood of dumping should be determined by considering various possible way in a situation of no actual known shipments during the current POI.
- (v) That the Designated Authority shall determine whether there is likelihood of recurrence of dumping.
- (vi) That no published information is available with regard to exports of the product under consideration from China to third countries, the Designated Authority may consider other option before concluding on likelihood of recurrence of dumping.
- (vii) that whenever exports have been made from China PR, the same were at dumped prices. Further, the Chinese exporters have been exporting salts of Chloroquine Phosphate. Likely dumping is established even if salt price is considered as price of the product under consideration (even though there would be substantial value addition).
- (viii) that given the legislative requirements in India, the Chinese producers cannot sell the product at prices higher than DPCO. In fact, they have to sell at lower prices only, as the DPCO is the price at which the imported product can be resold in the Country. The likelihood of dumping is also established at the DPCO price of the Chloroquine Phosphate prevailing during the investigation period.
- (vii) That the China does not have any significant consumption of the subject goods.

- (ix) That the imposition of anti dumping duties resulted in decline in imports and improvement in performance of the domestic industry during the injury period.
- (x) That the producers in China are having significant freely disposable production capacity for Chloroquine Phosphate and the India is one of the largest consumers of this product.
- (xi) That in view of the surplus capacities with the Chinese producers and likelihood of dumping considering the import prices of Chloroquine salts and DPCO prices, the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to recur if the duties are revoked in respect of imports from China.
- (xii) That anti dumping duties on the subject goods are required to be extended further for a period of five years;

#### Examination by the Authority

52. The present investigation is a sunset review and the Authority is required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continuation of or recurrence of dumping and injury. The Authority has taken note of all the issues raised by the domestic industry and other interested parties on disclosure statement and have dealt with at appropriate places in the final findings. The Authority has noted as under:

(i) There is no import of subject goods from China to India during POI and immediate previous year, therefore, no continued dumping.

(ii) Domestic industry in its written submission furnished the data for the period 1990-2007, on the reported malaria cases in South-East Asia and Western Pacific countries of WHO region. It has been noted from the World malaria Report for the year 2007 that during the year 2007 nil cases of malaria reported in respect of the country China as against 1476562 cases of malaria in respect of the country India. In addition to India and China 850 cases of malaria reported in respect of Bhutan and 59848 cases of malaria reported in respect of the country Cambodia. Authority notes that there is negligible demand/consumption of subject goods in China whereas there is huge demand of subject goods in India

(iii) The imports of the product under consideration from China have although ceased from 2005-06, the exporters in China P.R. are still having disposable capacities. Existence of significant production capacities in a situation where the demand for the product under consideration in China is almost nonexistent coupled with declining demand of the product in the global market increases the likely dumping from subject country.

**FINAL FINDINGS:**

53. Having regard to the contentions raised, information provided and submission made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- (i) Exporters/producers from subject country are treated as non-cooperative.
- (ii) Though there is no continued dumping but whenever exports have been made from China PR during injury period, the same were below domestic selling price.

(iii) The Authority after accessing data available on World Trade Atlas has found that product under consideration was earlier being imported under a specific code under 8 digit level i.e. 29392140 being unique code for this product. Subsequently, the Authority found no reported export under this unique ITC HS classification. However, at the 6 digit level with ITC HS 293921, the import volume of product "Quinine" which also includes the product under consideration (Chloroquine Phosphate) was in the vicinity of 76 MTS during 2004-05 and around 70 MTS during 2006-07. This indicates that imports of PUC have consistently been taking place at 6 digit level from the subject country. However, during POI, the imports reported in this data are only 4 MTs, which could be construed as a strategy so that imports do not get reported as exporters were aware about sunset review being due. To that extent withdrawal of existing anti dumping measures would open the floodgates for the Chinese producers, enable them to divert from other countries the product under consideration at dumped prices to India considering that the available spare capacity in China far exceed their total demand. It may also be worth a mention that because of inability of the domestic industry to capture imports in their data, total demand could not be assessed properly and in fact total demand has been calculated by taking commercial sale of domestic industry only.

(iv) In view of above, it is concluded that import of subject goods are still coming to India in the code of quinine and there is likelihood of recurrence of dumping, should the present measures be withdrawn.

(v) Further, should the present anti-dumping duties be revoked, injury to the domestic industry is likely to continue and intensify.

**Indian Industry's interest and other issues**

54. The Authority recognizes that the continuation of duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, continuation of anti dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practice, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority, notes that the continuation of the anti dumping measures would not restrict imports from subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The consumers could still maintain two or even more source of supply.

55. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

#### **Recommendations**

56. Having concluded that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on account of imports from China PR, if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that the measures is required to be extended in respect of imports from subject country, however quantum of anti-dumping duty in force need not be revised. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends to continuation of anti-dumping duty on import of subject goods from the subject country recommended vide Notification No. 14/3/2003-DGAD dated 15<sup>th</sup> July 2004 and imposed vide Customs Notification No. 84/2004-Custom dated 30<sup>th</sup> August, 2004 and further extended upto 02<sup>nd</sup> September 2009 vide Customs Notification No. 108/2008 - Custom dated 16<sup>th</sup> October, 2008.

R. GOPALAN, Designated Authority